अंग्रेजी सरकार के कुछ महत्वपूर्ण विस्तार क्षेत्र लॉर्ड वेलेजली (1798-1805 ई.)

- इसने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि पद्धति की शुरूआत की जिसके तहत निम्न राज्य सहायक संधि के भाग बन गए। जो निम्न है-
  1. हैदराबाद 1798 ई
  2. मैसूर 1799 ई.
  3. तंजौर 1799 ई.
  4. अवध 1801 ई.
  5. पेशवा 1802 ई.
  6. बरार व भोंसले 1803 ई.
  7. सिंधिया 1804 ई.
  8. अन्य राज्य - जयपुर, जोधपुर, मच्छेड़, बूंदी तथा भरतपुर।

लॉर्ड डलहौजी (1848-1856 ई.)

- डलहौजी ने हड़पनीति या व्यपगत के सिद्धांत के कारण निम्न राज्यों को ब्रिटिश राज का अंग बना लिया जो निम्नवत हैं-
  1. सतारा 1848 ई.
  2. जैतपुर (बुंदेलखण्ड)
  3. संभलपुर (उड़ीसा) 1849 ई.
  4. बघाट (हिमांचल प्रदेश) 1850 ई.
  5. उदेपुर (मध्य प्रदेश) 1852 ई.
  6. झाँसी (उत्तर प्रदेश) 1853 ई.
  7. नागपुर (महाराष्ट्र) 1854 ई.
- सन् 1856 ई. में डलहौजी ने अवध को कुशासन के आरोप पर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था।
- 1852 ई. में डलहौजी के समय लोअर वर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया।
- 1819 ई. में अंग्रेजों ने नेपाल पर आक्रमण किया और 1816 ई. में सुगौली की संधि द्वारा अंग्रेजों ने कुमाऊं, गढ़वाल और देहरादून के जिले गोरखा आक्रमणकारियों से लेकर ब्रिटिश राज्य में मिला लिया।
- इस प्रकार अपनी रणनीतिक व कूटनीतिक दक्षता, के तहत अंग्रेजों ने एक विशाल साम्राज्य को अपने नियंत्रण में कर लिया।

ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव :

- अंग्रेजों के भारत आगमन के पूर्व भी भारत में शक, कुषाण, गजनवी, सल्तनत कालीन, मुगल कालीन शासकों ने भी भारत में अधिकार किया लेकिन अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति ने भारत की अर्थव्यवस्था का अत्यन्त कमजोर कर दिया। इससे पूर्व के शासक भारत में ही बसकर इसी व्यवस्था के अंग बन गये थे। जबकि अंग्रेजो ने भारत से धन प्राप्त कर इंग्लैण्ड भेजने की नीति कर अनुसरण कर रहे थे। जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर दूरगामी व नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
- भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव 1757 के "प्लासी के युद्ध, के बाद पड़ी, जिसका प्रारम्भिक उद्देश्य यहां के उन साधनों को अपने कब्जे में लेना था, जिससे प्राप्त माल इंग्लैण्ड तथा अन्य यूरोपीय देशों में सरलता से बेचा जा सकें। उपनिवेशवाद का मूल तत्व आर्थिक शोषण में निहित है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद मुख्यतः तीन चरणों से गुजरा है जो इस प्रकार है-
  1. वाणिज्यिक चरण (1757 - 1813)
  2. औद्योगिक मुक्त व्यापार (1813 – 1858)
  3. वित्तीय पूँजीवाद (1860 के बाद)

1. **वाणिज्यिक चरण (1757- 1813):** इस चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। इस चरण में बंगाल व अन्य प्रांतों से वसूले गये भू-राजस्व के बचे हुए हिस्से से भारतीय माल को खरीदा जाता था और उसे अन्य देशों को अच्छी कीमत पर निर्यात किये जाने वाले माल के बदले कुछ भी नहीं लौटाया गया। इस तरह प्रतिवर्ष भारतीय माल और सम्पत्ति का दोहन होता रहा, परिणाम स्वरूप इंग्लैण्ड अमीर और भारत अधिक गरीब होता गया। भारत की लूट और इंग्लैण्ड में पूंजी संचय का प्रत्यक्ष परिणाम था कि इंग्लैण्ड औद्योगिक के दौर में प्रवेश कर गया। इस चरण की महत्वपूर्ण घटना 1813 का चार्टर अधिनियम था, जिसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया।
2. **औद्योगिक मुक्त व्यापार चरण (1813 - 1858):** इस चरण में भारत ब्रिटिश माल के मुक्त बाजार का केन्द्र बन गया। 1813 में कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तथा 1833 में कंपनी की समस्त वाणिज्यिक गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया अर्थात् अब ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश पूंजीपतियों को भारत में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति दे दी।
3. **वित्तीय पूंजीवाद का चरण (1860 के बाद):** इस चरण में अंग्रेजों द्वारा संचित अविराम धन को भारत में अपने व्यापारिक, सामाजिक हितों की पूर्ति के लिए रेल लाइनों के निर्माण, सड़कों के विकास और सिंचाई के साधनों के विकास में प्रयोग किया गया।

   इस चरण में पूंजी का निवेश सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र में किया गया।

   रेलवे लाइनों का विकास किया गया जिससे भारत के कच्चे माल को देश के अंदर के हिस्सों से बंदरगाहों तक पहुँचाया जा सके।

   भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास 1846 में लार्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन को 1853 में बम्बई से थाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाया गया।

   ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के इस तृतीय चरण में भारतीयों द्वारा भी कुछ भारतीय उद्योगों में पूंजी लगाई गई। भारतीय उद्योगों में सूती वस्त्र पहला उद्योग था जिसमें भारतीयों द्वारा पूंजी लगाई गई। इस समय गुजरात और बम्बई में महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केन्द्रों का विकास हुआ।

1. **भारतीय कृषि पर प्रभाव:**

   औपनिवेशिक काल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषिजन्य अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अंग्रेजो ने यहाँ के परम्परागत कृषि ढ़ाचें को नष्ट कर दिया और अपने हित के लिए भू-राजस्व निर्धारण और संग्रहण के नये तरीके लागू किये।

   प्लासी के युद्ध 1757 के पश्चात् बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद कंपनी के गर्वनर-जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में बंगाल में द्वैध-शासन व्यवस्था को समाप्त कर फार्मिंग सिस्टम (इजारेदारी प्रथा) की शुरूआत भू-राजस्व वसूली के लिए की। फार्मिंग सिस्टम' के अन्तर्गत कंपनी किसी क्षेत्र या उसे सौंपती थी, जो सबसे अधिक बोली लगाता था । इस व्यवस्था से किसानों का शोषण बढ़ गया ।

   क्लाइव के समय भू-राजस्व कर वार्षिक बंदोबस्त होता था । जिसे हेस्टिंग्स ने बढ़ाकर पांच वर्ष का कर दिया।

   बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्रचलित स्थायी भूमि बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया, जिन्हें अपनी जमींदारी वाले भू-क्षेत्र का पूर्ण भू-स्वामी माना गया।

2. **स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा**

   इस व्यवस्था के अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल कर 19% हिस्सा शामिल था। यह व्यवस्था 1793 में लागू की गयी थी।

   यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू था।

   इस व्यवस्था के तहत जमींदार जिन्हें भू-स्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, को अपने क्षेत्रों में भू-राजस्व की वसूली कर उसका दसवां अथवा ग्यारहवां हिस्सा अपने पास रखना होता था और शेष हिस्सा कंपनी के पास जमा करना होता था ।

इस व्यवस्था से कंपनी की आय का एक निश्चित हिस्सा तय हो गया, जिस पर फसल नष्ट होने का कोई असर नहीं पड़ता था। दूसरे जमींदार कंपनी के निष्ठावान बने रहे ।

स्थायी बंदोबस्त लार्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में प्रारंभ किया गया था।

3. रैय्यतवाड़ी व्यवस्था

इस व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरों और कैप्टन रीड को माना जाता है

1792 ई0 में कैप्टन रीड के प्रयासों से रैय्यतवाडी व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडू के 'बारामहल जिले में लागू किया गया।

तमिलनाडू के अलावा यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से पूर्वी बंगाल असम, कुर्ग के कुछ हिस्से में लागू की गयी

इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश भारत भू-क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था।

रैयतवाड़ी व्यवस्था में कृषक ही भूमि का स्वामी होता था जिसे भूमि की कुल उपज का 55% से 33% के बीच लगान कंपनी को अदा करना होता था।

इस व्यवस्था में लगान की वसूली कठोरता के साथ की जाती थी, परिणामतः किसान महाजनों के चंगुल में फंसता गया ।

1836 के बाद रैय्यतवाड़ी व्यवस्था में बिंगेर और गोल्डस्मिथ द्वारा कुछ सुधार किया गया, अब खेत के लिए उपलब्ध साधनों के आचार पर खेती का लगान निश्चित किया गया, जिसका रैय्यत व कम्पनी दोनों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा।

4. महालवारी बंदोबस्तः

स्थायी एवं रैयतवाड़ी व्यवस्था की असफलता के बाद 'महालवारी व्यवस्था को लागू किया गया।

महालवारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के 30% हिस्से पर लागू थी। इस व्यवस्था के अर्न्तगत दक्कन के कुछ जिले उत्तर भारत (संयुक्त प्रान्त) आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे।

इस व्यवस्था में भू-राजस्व का निर्धारण 'महाल' या समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। महाल के समस्त कृषक भू-स्वामियों के भू-राजस्व का निर्धाण संयुक्त रूप से किया जाता था जिसमें गांव के लोग अपने मुखिया या प्रतिनिधियों के द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर लगान की अदायगी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते थे।

इस व्यवस्था का परिणाम ग्रामीण समुदाय के विखण्ड के रूप में सामने आया। सामाजिक दृष्टि से यह व्यवस्था विनाशकारी और आर्थिक दृष्टि से विफल सिद्ध हुई।

5. विऔद्योगिकीकरण (Deindustrialization)

भारत में 1800 से 1850 के बीच के समय को औद्योगिकीकरण के नाम से जाना जाता है। विऔद्योगिकीकरण के नाम से जाना जाता है। विऔद्योगिकीकरण के इस दौर में जहां ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था वही भारत में औद्योगिक पतन का दौर चल रहा था। इस दौर में भारतीय परम्परागत हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास हुआ। जिसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव यह हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था अधिकारिक विदेशी अर्थव्यवस्था के आधिपत्य में आ गई।

1765-1785 के बीच इंग्लैण्ड में हरग्रीब्ज ने कताई की मशीन, जेम्सवाट ने भाप का इंजन, आर्कराइट ने वाटरफेंम व कार्टराइट ने पावरलूम का अविष्कार किया। ऐसे में भारतीय परम्परागत उद्योग इस आधुनिक मशीनों के समान परिणाम नहीं दे पाये। एक ओर भारत में परम्परागत हथकरघा उद्योग विनष्ट हो रहे थे, तो दूसरी तरफ काम के अभाव में शिल्पकार एवं कारीगर गांव की ओर लौट रहे थे, जिससे कृषि अर्थव्यवस्था भी पतन की ओर अग्रसर हुई।

1853 में कवास जी नाना भाई ने बम्बई के भड़ौच नामक स्थान पर प्रथम सूती मील की स्थापना की। 1855 में जूट मिल बंगाल के रिसरा में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा स्थापित किया गया। 1907 में टाटा आयरन स्टील कम्पनी की स्थापना जमशेदपुर में हुई। इन प्रयासों के बावजूद भारतीय उद्योग ब्रिटिश कम्पनी के सामने टिक नहीं पाये और नष्ट हो गये।

दादा भाई नौरोजी एवं धन के निष्कासन का सिद्धान्त

भारत की बढ़ती निर्धनता की कीमत पर अपने को सम्पन्न बनाने के लिए ब्रिटेन द्वारा भारत के कच्चे माल, संसाधनों और धन को निरन्तर 'लूटमार' की पृष्ठभूमि को दादा भाई नौरोजी और रानाडे जैसे राष्ट्रवादों ने 'धन के बर्हिगमन या निष्कासन' की संज्ञा दी।

दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने पेपर "England debt to India" को पढ़ते हुए सर्वप्रथम 'धन के बर्हिगमन' का सिद्धांत प्रस्तुत किया।

कालांतर में पावर्टी एण्ड अन ब्रिटिश रूल इन इण्डिया (1867), द वॉन्टस एण्ड मीन्स ऑफ इण्डिया 1870 और ऑन दी कॉमर्स ऑफ इण्डिया 1871, द्वारा धन के निष्कासन सिद्धान्त की व्याख्या दादा भाई नौरोजी ने की।

दादा भाई नौरोजी ने भारत की गरीबी व अकाल की समस्या का कारण उपनिवेशवाद व धन की निष्कासी को बताते हुए 6 कारकों का उल्लेख किया है।

1. भारत पर बाह्य शासन एवं प्रशासन
2. ब्रिटेन का जो भी प्रशासन एवं व्यवस्था थीं उस पर खर्च भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारित होता था।
3. ब्रिटिश साम्राज्य में घटने वाली कोई भी आर्थिक घटना भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करती थी।
4. मुक्त व्यापार के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पडा।
5. भारत में अधिकतर पूंजीपतियों का विदेशी होना।
6. विदेशी पूंजीपतियों को कच्चा माल एवं सस्ता श्रम तो भारत से प्राप्त हो जाता था पर लाभ वे अपने देश भेज देते थे।

दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन, भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है।

दादा भाई नौरोजी ने धन की निकासी पर एक के एक बाद चार निबन्ध लिखे जो इस प्रकार है -

1. इंग्लैण्ड डेब्ट टू इण्डिया
2. दि वाट्स एण्ड मिन्स ऑफ इण्डिया
3. ऑन द कॉमर्स ऑफ इण्डिया
4. पावर्टी एण्ड अनब्रिटिश रूल इन इण्डिया

अर्थव्यवस्था सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

देश का पहला अकाल उत्तर प्रदेश में 1860-61 में पड़ा जिसमें 20 लाख लोगों की जान गई।

1865-66 में अकाल का प्रभाव उड़ीसा, बंगाल, बिहार तथा मद्रास में पड़ा जिसमें लगभग 20 लाख लोग काल के गाल में समा गये।

इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए किया गया।

भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति को कार्ल मार्क्स ने घिनौना कहा है।

सर सैय्यद अहमद खां, दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासी सिद्धान्त पर विश्वास नहीं करते थे।

बिहार में 'परमानेंट सेटिलमेंट' लागू करने का कारण भू-राजस्व का राजस्व निर्णय करना था।

अंग्रेजों ने रैय्यतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसीडेंसी में आरंभ की थी।

दादा भाई नौरोजी, जी. सुब्रमण्यम् अय्यर तथा आर. सी. दत्त ने भारत में उपनिवेशवाद की आलोचना की थी।

सर टॉमस मुनरों ने रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी।

1885 ई0 में बंगाल, बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था।

रैय्यवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बंबई प्रेसीडेंसी में लागू था।

असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ई0 में की गयी थी।

इस्तमरारी बन्दोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू किया था।

दादा भाई नौरोजी को प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता माना जाता है। जबकि राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आंकलन डॉ० वी. के. आर.वी. राव ने किया।

दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20रू अनुमानित की थी।

आर. सी. दत्त की पुस्तक 'इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' को भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है।

1901 में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण करते हुए 'गोपाल कृष्ण गोखले' ने 'धन के बर्हिगमन' सिद्धान्त को प्रस्तुत किया।

रजनी पाम दत्त की पुस्तक 'इंडिया टुडे' ने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के विभिन्न चरणों का उल्लेख मिलता है।

भारतीय इतिहास का सर्वाधिक भयंकर अकाल 1876–78 में मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, महाराष्ट्र पश्चिमी संयुक्त प्रांत और पंजाब में पड़ा।